NEW ERA AGRICULTURE MAGAZINE

सशक्त किसान, समृद्ध भारत: किसानों की आय बढ़ाने के प्रभावी उपाय

ओमकार गुप्ता

परिचय: -

भारत में किसानों की आय को दोगुना करने की आवश्यकता कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से उत्पन्न होती है, जिनका सामना ग्रामीण समुदायों को करना पड़ता है। हालांकि कृषि भारत की आधी से अधिक आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत है, फिर भी किसानों की आय कम और अस्थिर है, जो बढ़ती लागत और कम उत्पादन कीमतों का परिणाम है। बीज, उर्वरक, कीटनाशक और श्रम जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि किसानों को उनके उत्पादन के लिए मिलने वाली कीमत अक्सर इन खर्चों को पूरा करने में भी नाकाफी रहती है। इस कारण से अधिकांश किसान मामूली लाभ या घाटे में रह जाते हैं। इसके अलावा, छोटे और बंटे हुए खेतों का होना भी एक प्रचलित समस्या है - लगभग 85% भारतीय किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है, जिससे उत्पादन लागत को कम करना मुश्किल हो जाता है। कम लाभप्रदता ने किसानों में उच्च स्तर का ऋण भी पैदा किया है, जिसे अक्सर अनौपचारिक, उच्च ब्याज दर वाले साहूकारों से लिया जाता है, जिससे किसान आर्थिक संकट के चक्र में फंसे रहते हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कारण है। किसानों की आय शहरी कामगारों की तुलना में काफी कम है, जिससे ग्रामीण-शहरी आय का एक बड़ा अंतर उत्पन्न हुआ है और विशेषकर युवा पीढ़ी बेहतर आय के अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रही है। कमजोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा, सीमित सड़क नेटवर्क, अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं और कोल्ड चेन की कमी इस अंतर को और बढ़ा देती हैं, जिससे किसानों को उचित बाजार मूल्य तक पहुंचने में कठिनाई होती है और खराब होने वाले उत्पादों के नुकसान का सामना करना पड़ता है। सूखा, बाढ़ और अनियमित वर्षा जैसे जलवायु जोखिम आय को और भी अस्थिर करते हैं, वहीं सूखे क्षेत्रों में जल-गहन कृषि जैसे अस्थिर संसाधन उपयोग से भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे लंबे समय तक कृषि की व्यवहार्यता को खतरा है।

इस पृष्ठभूमि में, किसानों की आय को दोगुना करने पर ध्यान केंद्रित करना, गरीबी और असमानता को कम करने, ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने और व्यापक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय रूप से सशक्त किसान न केवल भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति में सुधार करके आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देंगे। बढ़ी हुई आय के साथ, किसान अपने खेतों में पुनः निवेश कर सकेंगे, उन्नत तकनीकों, बेहतर प्रथाओं और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को अपनाकर उत्पादन और दक्षता को बढ़ा सकेंगे। इस प्रकार, किसानों की आय को दोगुना करना सिर्फ एक आर्थिक उद्देश्य नहीं है; यह एक आवश्यक कदम है जो एक स्थायी और समावेशी कृषि प्रणाली के निर्माण की दिशा में ग्रामीण समुदायों को

ओमकार गुप्ता
सहायक प्राध्यापक (Ad-hoc), कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय
वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभणी (महाराष्ट्र)

सशक्त बनाता है, जलवायु जोखिमों को कम करता है, और दीर्घकालिक विकास और स्थिरता के लिए टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

भारत में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने, बेहतर बाज़ार पहुँच, और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख उपाय दिए गए हैं जो भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक हो सकते हैं:

1. **उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक खेती तकनीक**
   - ⇨ **प्रिसीजन एग्रीकल्चर**: ड्रोन, जीपीएस, और IoT जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग कर खाद, पानी, और कीटनाशकों का सही मात्रा में उपयोग कर लागत को कम कर और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।
   - ⇨ **बेहतर बीज किस्में**: उच्च उत्पादन, सूखा और रोग-प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।
   - ⇨ **सिंचाई के नवीन तरीके**: ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ अपनाकर पानी का उपयोग कुशलतापूर्वक किया जा सकता है।
2. **कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा**
   - ⇨ **सस्ता यंत्रीकरण**: छोटे और सीमांत किसानों को मशीनों की रेंटल सुविधा प्रदान कर, कम लागत पर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।
   - ⇨ **कस्टम हायरिंग सेंटर**: इन केंद्रों के माध्यम से किसान उपकरण किराये पर लेकर अपने उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं।
3. **आय के स्रोतों में विविधता**
   - ⇨ **बागवानी, पशुपालन, और मत्स्य पालन**: फल-सब्जी उत्पादन, डेयरी, और मत्स्य पालन से किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बन सकते हैं।
   - ⇨ **कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्र**: मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, कुक्कुट पालन आदि जैसे क्षेत्रों में भी किसानों के लिए आय के अवसर हैं।
4. **मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण**
   - ⇨ **फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स**: छोटे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित कर कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलकर किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।
   - ⇨ **कृषि उद्यमिता**: स्थानीय उत्पादों का पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर किसानों को बाजार में बेहतर कीमत मिल सकती है।
5. **मजबूत बाज़ार और विपणन संबंध**
   - ⇨ **किसान उत्पादक संगठन (FPO)**: FPOs से किसान सामूहिक रूप से काम कर सकते हैं, जिससे उन्हें मोलभाव की शक्ति मिलती है और बेहतर कीमत मिलती है।
   - ⇨ **ई-बाज़ार प्लेटफार्म**: ई-नाम जैसे ऑनलाइन बाज़ारों का विस्तार कर किसानों को अधिक बाज़ार तक पहुँच प्रदान की जा सकती है।
   - ⇨ **कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग**: कॉर्पोरेट्स के साथ अनुबंध खेती के जरिए किसानों को सुनिश्चित कीमत मिल सकती है।
6. **बेहतर मूल्य प्राप्ति और बीमा कवरेज**
   - ⇨ **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)**: MSP की नीति को और अधिक फसलों तक पहुँचाकर किसानों के लिए न्यूनतम आय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

- **फसल बीमा**: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार कर अधिक फसलों को कवर कर किसानों की आय को जलवायु जोखिमों से सुरक्षित किया जा सकता है।
- **मूल्य स्थिरीकरण निधि**: प्रमुख फसलों के मूल्य में गिरावट के समय किसानों को समर्थन देने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि बनाई जा सकती है।

7. इनपुट लागत को कम करना

- **जैविक और प्राकृतिक खेती**: जैविक और शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम होगी।
- **सब्सिडी वाले इनपुट्स**: सरकार से रियायती दर पर बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट मिलने से किसानों की लागत घट सकती है।

8. एग्री-टेक और नवाचार को बढ़ावा

- **डिजिटल प्लेटफार्म और मोबाइल ऐप्स**: मौसम, फसल के दाम, और कीट नियंत्रण की जानकारी देने वाले ऐप्स के माध्यम से किसानों को सही निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।
- **एग्री-टेक स्टार्टअप्स**: नए स्टार्टअप्स जो एग्री-टेक, AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन पर काम करते हैं, किसानों की उत्पादकता और बाज़ार पहुँच में सुधार कर सकते हैं।

9. ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास

- **भंडारण और वेयरहाउसिंग**: आधुनिक भंडारण सुविधाएँ बनाकर कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
- **कोल्ड चेन विकास**: फलों, सब्जियों और डेयरी उत्पादों के लिए कोल्ड चेन की स्थापना से गुणवत्ता बनी रहती है और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकती है।

10. वित्तीय साक्षरता और ऋण की पहुंच

- **सस्ती ऋण उपलब्धता**: किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से उनकी ऋण पर निर्भरता घटाई जा सकती है।
- **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम**: किसानों को वित्तीय प्रबंधन, निवेश और बचत की शिक्षा देकर उन्हें बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सकता है।

11. सरकारी योजनाओं और नीतियों का विस्तार

- **योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन**: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और मृदा स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन किसानों के लिए सहायक हो सकता है।
- **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)**: DBT से किसानों को सब्सिडी और लाभ सीधे पहुँचाया जा सकता है, जिससे बिचौलियों और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

इन सभी रणनीतियों का समेकित रूप से कार्यान्वयन न केवल किसानों की आय को दोगुना करेगा, बल्कि भारतीय कृषि को अधिक मजबूत, कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। आय बढ़ने से किसानों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि होगी, जिससे ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ेगी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान होगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर आय से सामाजिक स्थिरता भी आएगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और समाज का

समग्र विकास होगा। इस प्रकार, किसानों की आय को दोगुना करना न केवल एक आर्थिक लक्ष्य है, बल्कि यह भारत के ग्रामीण समुदायों के जीवन में सुधार और राष्ट्रीय प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान है।